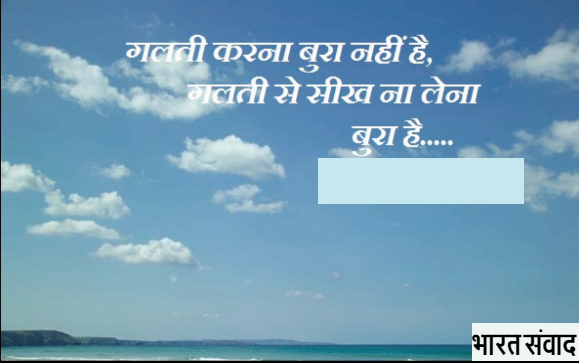


सम्पादकीय

तर्कसंगत जीएसटी, व्यापक सुधार से ही लाभ

भारत के समक्ष उनकी मनमानी टैरिफ नीति का डटकर मुकाबला करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह अच्छा है कि भारत ऐसा ही कर रहा है लेकिन इसी के साथ यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि भारतीय कारोबार जगत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बने। उसे जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों का लाभ उठाकर खुद को सक्षम बनाना होगा। प्रधानमंत्री की ओर से लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में व्यापक सुधार की घोषणा के अनुरूप वस्तु एवं सेवा कर को तर्कसंगत बनाने के लिए पकित समूह ने 5 और 18 प्रतिशत के केवल दो स्लैब के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का जो अनुमोदन किया, उसे सभी राज्यों की सहमति मिलनी चाहिए। जीएसटी की 12 और 28 प्रतिशत वाली श्रेणियां हटाकर केवल 5 और 18 प्रतिशत वाली दो श्रेणियां समय की मांग हैं। इसकी जरूरत इसलिए भी जताई जा रही थी, क्योंकि इससे एक तो जटिलता बढ़ रही थी और दूसरे, रोजमर्रा की कुछ आवश्यक वस्तुएं महंगी भी थीं। जीएसटी के दो स्लैब का लाभ केवल आम आदमी को ही नहीं, कारोबार जगत को भी मिलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि राजस्व में आने वाली फौरी कमी आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि तंबाकू जैसे अहितकारी एवं लकजरी कारों समेत अन्य चुनिंदा विलासी मानी जाने वाली वस्तुओं पर से उपकर हटाकर 40 प्रतिशत की एक विशेष श्रेणी का प्रस्ताव किया गया है। आशा है कि जीएसटी काउंसिल इसी दिशा में आगे बढ़ेगी और फैसले लेगी, लेकिन केवल दो स्लैब वाला जीएसटी ही पर्याप्त नहीं। इसके साथ ही इस टैक्स व्यवस्था में अन्य अपेक्षित बदलाव भी किए जाने चाहिए, ताकि कारोबारियों को अधिक कागजी काम न करने पड़ें और टैक्स चोरी भी रुके एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला। जीएसटी चोरी के खिलाफ सख्ती बरती ही जानी चाहिए, लेकिन उसके कारणों की तह तक भी जाना होगा। उचित यह भी होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों शराब और पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करें। यह भी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि जीएसटी के साथ ही अन्य आर्थिक सुधारों पर भी तेजी से आगे बढ़ा जाए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर नए दौर के आर्थिक सुधारों के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाने की जो घोषणा की, उस पर अमल होते हुए दिखना चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रखा है। वे भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत के समक्ष उनकी मनमानी टैरिफ नीति का डटकर मुकाबला करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह अच्छा है कि भारत ऐसा ही कर रहा है, लेकिन इसी के साथ यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि भारतीय कारोबार जगत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बने।

आज का विचार



मेघ राशि : दिन मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके पक्ष में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही, आप अपने व्यवहार और मधुर वाणी से किसी भी स्थिति को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी करने वालों का दिन भी अच्छा रहने वाला है।

वृषभ राशि : समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और व्यापार के मामले में कोई शुभ समाचार सुनने को भी मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपकी भुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है

मिथुन राशि: व्यापार और नौकरी के मामले में दिन शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी के सहयोग और समर्थन से आपकी उत्तम संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। वहीं, पिता से भी किसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति होने की संभावना है।

कर्क राशि: आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। आपको कहीं से अचानक बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। व्यापार के मामले में आपकी रुकी हुई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी।

सिंह राशि : राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापार के मामले में कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्य अब पूरे हो सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे।

कन्या राशि : कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहने, मेहनत और लगन के साथ काम करने से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही, लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है।

तुला राशि: विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा या किसी प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इसी के चलते मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी

करने वालों की समझदारी के चलते उनका मान-सम्मान बढ़ेगा और आय के नए स्रोत बनने से खुश रहेंगे।
वृद्धिक राशि: आर्थिक मामलों में दिन उत्तम रहेगा और आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी। धन लाभ के शुभ संयोग बनते जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। कार्यक्षेत्र में अगर कोई काम लंबे समय से रुका था तो वह अब पूरा हो सकता है।

धनु राशि : सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होगी और घर के जरूरत के सामान खरीदने पर भी आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन व्यापार में आपको धन के मामले में किसी भी प्रकार की लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में फैसले लेने से पैसा फंसने की संभावना है।

मकर राशि: व्यवसाय के क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा और लाभ कमाने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में भी दिन अच्छा रहने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। आप व्यवसाय में परिवर्तन की योजना भी बना सकते हैं।

कुंभ राशि : आपका दिन सामान्य से कम अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या होने के संकेत हैं। ऐसे में ज्यादा भागदौड़ करनी में सावधान रहना होगा। बिना सोचे-समझे फैसले लेने से नुकसान हो सकता है।

मीन राशि: बिजनेस के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। कामधंधे उन्नति प्राप्त होने से आप पूरा दिन खुश रहेंगे और उत्साह से भरपूर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यापार में पास या दूर की किसी यात्रा से लाभ हो सकता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले माता-पिता आशीर्वाद लेना लाभदायक रहेगा

ज्योतिष सेवा केंद्र
ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

आवश्यक रक्षा कवच है सुदर्शन चक्र, वैश्विक सुरक्षा-सामरिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदला



आत्मनिर्भरता का

भाव बढ़ाने के साथ ही

यह सतह हवा और

समुद्र से भी संचालन-

प्रक्षेपण में सक्षम

होगा। इसका

पुनउपयोग भी किया

जा सकेगा। इसका

नियंत्रण भी चीफ

आफ डिफेंस स्टाफ-

सीडीएस के माध्यम

से होगा। इसमें कोई

संदेह नहीं है कि जब

सुदर्शन चक्र नाम

वाली रक्षा प्रणाली

प्रभाव में आएगी तो

हमारे सामरिक ढांचे

का प्रमुख स्तंभ

बनेगी।

पा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने

संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं कीं। ऐसी ही एक घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले दस वर्षों के दौरान स्वदेशी तकनीकी विकास के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का सुरक्षा कवच मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरणा लेते हुए हमने सुदर्शन चक्र की राह चुनी है। इस तंत्र से संबंधित समस्त शोध, विकास एवं विनिर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह भी एक संयोग ही है कि भारत की प्रमुख स्ट्राइक कोर में से एक 21 कोर को भी सुदर्शन चक्र ही कहते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित यह आक्रामक इकाई दुश्मन को उसके इलाके में गहरी चोट पहुंचाने की क्षमताओं से लैस है। पिछले कुछ समय में वैश्विक सुरक्षा-सामरिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदला है और निरंतर परिवर्तनों से गुजर रहा है। इस परिदृश्य में मिसाइल डिफेंस प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों का आधार स्तंभ बन गई है। इस क्रम में उन्नत तकनीकें मिसाइल खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, इंटरसेप्ट करने और निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इनके काम का दायरा छेटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर अंतरमहाद्वीपीय



बैलिस्टिक मिसाइलों यानी आइसीबीएम तक फैला हुआ है। भू-राजनीतिक (जियो-पॉलिटिकल) तनाव बढ़ने की स्थिति में जब मिसाइलों का चलन बढ़ता है, तब सशक्त मिसाइल रक्षा प्रणालियों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस कड़ी में इंजरायल की आयरन डोम प्रणाली का अवसर उदाहरण दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस साल एलान किया कि वे 175 अरब डालर की लागत से तैयार होने वाली गोल्डन डोम प्रणाली से अमेरिका के रक्षा आवरण को और अभेद्य बनाएंगे। गोल्डन डोम की संकल्पना स्थल, समुद्र और अंतरिक्ष आधारित मिसाइलों को निष्प्रभावी करने को ध्यान में रखकर की गई है। रूस ए-135 एंटी-बैलिस्टिक प्रणाली के जरिये मास्को और अन्य महत्वपूर्ण शहरों की रक्षा करता है। उसके पास एस-400 जैसी कारगर प्रणाली भी है जो तमाम मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। भारत के पास भी एस-400 की तीन स्क्वाड्रन हैं, जिसमें दो स्क्वाड्रन का और जुड़ाव होना है।

चीन के पास एक्च्यू-9 जैसी प्रणाली है। सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की यह एंटी-बैलिस्टिक क्षमता प्रणाली एक तरह से रूसी एस-300 का ही चीनी संस्करण है। विमान, क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल बैलिस्टिक जैसे हवाई खतरों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम इस प्रणाली को चीन ने पाकिस्तान, मोरक्को, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को बेचा भी है। ताइवान और जापान के पास भी ऐसी ही प्रणालियां हैं। ताइवान के पास जहां स्काईबो श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है, वहीं जापान की योजना अमेरिका के पीएसी-3 वाले सतह से हवा में सक्रिय होने वाले इंटरसेप्टर्स को अपनाने की है। अन्य प्रमुख देशों की तरह भारत भी मिसाइल संबंधी खतरों और साइबर हमलों के प्रति अपना रक्षा कवच मजबूत बनाने में लगा है। आपरेशन सिंदूर में इस रक्षा कवच का प्रभावी असर भी देखने को मिला। इंडीग्रेटेड एयर कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम यानी

आइएसीसीएस के जरिये भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। अनुमान है कि प्रस्तावित सुदर्शन चक्र को भारत के मौजूदा हवाई सुरक्षा ढांचे से भी जोड़ा जाएगा। इसे मूल रूप से आइएसीसीएस के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमें सेना के स्वदेशी आकाशतीर नेटवर्क का भी समावेश होगा। सुदर्शन चक्र में अत्याधुनिक निगरानी, इंटरसेप्शन और प्रतिकार करने की क्षमताएं होंगी। यह हवा में, स्थल पर या समुद्र के साथ-साथ साइबर स्पेस से दस्तक देने वाले किसी भी खतरे को तत्काल निष्प्रभावी करने में सक्षम होगा। माना जा रहा है कि सुदर्शन चक्र की क्षमताएं पारंपरिक मिसाइल डिफेंस से भी कहीं अधिक होंगी। वर्तमान में जिस तरह के नए-नए खतरे बढ़े हैं, उसे देखते हुए सैन्य एवं तकनीकी रक्षा कवच को और मजबूत बनाया जाना अपरिहार्य हो गया है। याद रहे कि आधुनिक समर नीति में केवल सैन्य प्रतिष्ठान ही नहीं, बल्कि बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क,

खाद्य एवं जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और रक्षा प्रणालियां भी निशाने पर होती हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र जैसे ढांचे की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। इसमें सैन्य तकनीकों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों की भी अहम भूमिका होगी। वैसे तो मिशन सुदर्शन चक्र की रूपरेखा अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, पर इसमें भारत की प्रतिष्ठित अनुसंधान इकाइयों, रक्षा प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र की सहभागिता-सक्रियता देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह आकाश, एस-400 और क्यूआर-सैम जैसी मौजूदा प्रणालियों के साथ-साथ लेजर-आधारित इंटरसेप्टर जैसी भविष्य की ताकत से संचालित होकर एक संयुक्त रक्षा प्रणाली की भूमिका निभाएगा। इसे प्रभावी जवाबी हमलों की क्षमताओं के साथ ही हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटने की दृष्टि से भी तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ाने के साथ ही यह सतह, हवा और समुद्र से भी संचालन-प्रक्षेपण में सक्षम होगा। इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकेगा। इसका नियंत्रण भी चीफ आफ डिफेंस स्टाफ-सीडीएस के माध्यम से होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब सुदर्शन चक्र नाम वाली रक्षा प्रणाली प्रभाव में आएगी तो हमारे सामरिक ढांचे का प्रमुख स्तंभ बनेगी। एक निरंतर जटिल होते सुरक्षा परिदृश्य में अत्याधुनिक तकनीकों के जुड़ाव से उभरते हुए खतरों से निजात दिलाने में यह प्रणाली अहम भूमिका निभाकर भी अपनी उपयोगिता साबित करेगी।

विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का

ललित गर्ग



गंभीर अपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो जरूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्रसम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक और हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामे को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था से इस्तीफा देने या सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बजाय सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही प्रवृत्ति जनता के विश्वास को तोड़ती है और राजनीति

बल्कि अनिवार्यता है। जब सत्ता और शासन के केंद्र में अपराधी मानसिकता के लोग बैठते हैं, तो वे शासन को अपने स्वार्थ और अपराधों की ढाल बना लेते हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था खोखली होती है, बल्कि आम जनता का जीवन भी संकट में पड़ता है। भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल, भाई-भतीजावाद, हिंसा और अनैतिकता का वातावरण उसी समय पनपता है, जब राजनीति अपराधियों के कब्जे में जाती है। ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की मांग आज पहले से अधिक बढ़ गई है। जनता ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें। राजनीति यदि सेवा और त्याग का माध्यम बनेगी तो ही समाज का कल्याण होगा। जिन नेताओं पर जरा भी संदेह का धुंधलका हो, उन्हें स्वयं स्वेच्छ से पद छोड़ देना चाहिए। यही परंपरा राजनीति को उच्चता और गरिमा प्रदान कर सकती है। अपराधमुक्त राजनीति केवल नैतिक अपेक्षा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूरी है। जब तक राजनीति में शुचिता और नैतिकता का स्थान नहीं बनेगा, तब तक सुशासन और ईमानदार प्रशासन की कल्पना अधूरी ही रहेगी। नए कानूनों का निर्माण कर अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद करना समय की सबसे बड़ी मांग है। यह कदम न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जनता के भीतर यह विश्वास भी जागरेगा कि राजनीति वास्तव में लोककल्याण के लिए है, न कि अपराधियों की शरणस्थली। यही अपराधमुक्त राजनीति का दर्शन है, जहां

सत्ता अपराधियों का आश्रय-स्थल न होकर समाज की नैतिक ऊर्जा का केंद्र बने। यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वह लोकतंत्र को उसकी वास्तविक आत्मा लौटाए और राजनीति को सेवा, शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाए।

भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों से राजनीति और अपराध के गठजोड़ को लेकर गहरी चिंता लगातार उठती रही है। जनता बार-बार यह अपेक्षा करती है कि जिनमें वे संसद और विधानसभा भेजते हैं, वे न केवल ईमानदार और पारदर्शी हों बल्कि उनके चरित्र और आचरण पर कोई दाग न हो। किंतु बार-बार यही देखने को मिलता है कि गंभीर अपराधिक मामलों में फंसे नेता भी उच्च पदों पर बने रहते हैं और शासन-सत्ता का उपयोग अपने बचाव के लिए करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया नया विधेयक (संविधान का 130वां संशोधन) एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, केन्द्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार एवं अपराध विरोध बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं। उनकी असहमति अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रही है कि आखिर विपक्ष दागियों की कलालत करते हुए वह स्वयं भी दागी क्यों बन रही है? आशंका जताई जा रही है कि यदि यह संशोधन पारित हो गया तो विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्री अस्थिर हो सकते हैं, उनके पद संकट में पड़ सकते हैं।

दरअसल वह विरोध केवल विधेयक का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सुविधा, अपनी सत्ता बचाने और सुरक्षा का है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में अपराधमुक्त राजनीति नहीं चाहता? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को अपराधियों का अड्डा बनाए रखना आवश्यक है?

विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है, और केवल आरोप लगाकर भी नेताओं को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है

अशिक्षा जनित अंधविश्वास, समग्र विकास में अवरोध।

संजीव ठाकुर

आश्चर्य की बात है कि आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से शिक्षित जनमानस भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंधभक्त या अनुयाई हो गया है। मकान में वास्तु दोष दूर करने के लिए अनावश्यक तोड़फोड़ और सुधार के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। यह अंधविश्वास का एक जीता जागता प्रमाण है। वास्तु दोष तथा अंधविश्वास को मानने वाले 90% शिक्षित युवा इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा और अज्ञानता ने अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता को भारत में फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। इस वैज्ञानिक युग में अत्यंत शिक्षित एवं पढ़े-लिखे लोग भी अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता के पीछे भागने लगे तो यह समाज और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। वास्तु दोष तथा अंधविश्वास के विवेकपूर्ण विचारों को सोचने की शक्ति प्रदान करता है और इसके पश्चात ही मनुष्य वैज्ञानिक आधार पर तर्क रखकर अपनी बात को मानना शुरू करता है। पूर्व में हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है अब लोगों ने लॉजिक और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह मान लिया है कि पृथ्वी गोल ही है शहीद भगत सिंह ने आजादी के लिए एक संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके घोषणा पत्र में कहा था कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति के बहुत बड़े बाधक है, वह हमारे रास्ते की बाधा साबित हुए हैं उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए जोकि आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए इसी प्रकार अन्य बहुत सारी कमजोरियां भी हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करना होगा, इस कार्य के लिए सभी समुदाय के

क्रांतिकारी उत्साह रखने वाले नई सोच के नौजवानों की आवश्यकता है।हू उन्होंने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि युवा शक्ति ही देश में नए विचारों की क्रांति ला सकती और अंधविश्वास को समूल नष्ट करने में इनकी ऊर्जा इस कार्य के लिए लगाई जा सकती है, पर दूसरी तरफ शिक्षा का प्रचार प्रसार होना भी नितांत आवश्यक है।हू शिक्षा ही ऐसा मूल मंत्र है जिससे अंधविश्वास एवं आडंबर की पोल खोली जा सकती शिक्षा से हमारा तात्पर्य विज्ञान से भी है विज्ञान ने अनेक अंधविश्वास को जन सूचियों में अविश्वास के रूप में में स्थापित किया है और शिक्षा तथा धार्मिक कट्टरता को भारत में फैलाने में जिन से बलक हम न सिर्फ चांद पर पहुंचे हैं बल्कि अज्ञानता प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया एक परिवार की तरह एक दूसरे के एकदम करीब आ चुकी है ऐसे में अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद की जगह कहीं बच जाती है भला ? शिक्षा का स्तर ईतना ऊंचा हो जाना चाहिए की इन अंधविश्वासी बातों और मिथकों का अस्तित्व ही मूल रूप से विस्मृत किया जाना चाहिए।हू बिल्ली के रास्ता काटने से काम शुरू जाता है, किसी की छींक देने से अशुभ संकेत स्थापित होने लगते हैं यदि कौवा बोलता है तो मेहमान आने का संकेत माना जाना इन सब बातों की कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है और इन विचारों का अस्तित्व ही मूल रूप से विस्मृत किया जाना चाहिए।हू शिक्षा विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान समाज में तर्कसंगत बातों का विश्वास करने पर भरोसा दिलाता है और धीरे धीरे अंधविश्वास को तथा धार्मिक कट्टरता से मनुष्य को दूर ले जाता है। मूलतः अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें शिक्षा जैसे अस्त्र का इस्तेमाल तोत्र गति से किया जाना चाहिए।



टेक और डिजिटल के बदलते युग में जॉब मार्केट में प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बदलती जा रही है। आईटी सेक्टर के साथ-साथ लगभग सभी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स को अच्छे खासे पैकेज पर हायर किया जा रहा है। यही वजह है कि कॉलेज प्लेसमेंट सेशन में भी बीटेक ईसीई डिग्री वालों का प्लेसमेंट पैकेज सबसे तगड़ा मिलने लगा है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स आज के टेक और डिजिटल युग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बदलते जॉब मार्केट में कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हों। आईटी सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और हेल्थकेयर तक में ईसीई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी है। यही कारण है कि कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान बीटेक ईसीई स्टूडेंट्स को हार्ड सैलरी पैकेज मिल रहे हैं। तकनीकी ज्ञान और मल्टी-डोमेन स्किल्स के चलते ये ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं।

बीटोक इसीसी का पूरा नाम सेचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो चार वर्षीय ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है। बीटोक इसीसी छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिवाइस कम्युनिकेशन, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डेटा और सिग्नल को अलग-अलग माध्यमों से भेजने की तकनीक सीखी जाती है। यह कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोनों का मेल है, जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग में स्किल देता है। यह फील्ड 5जी, सैटेलाइट, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों में करियर के अच्छे मौके देती है।

बीटेक ईसीई में इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय, सिग्नल और सिस्टम, एनालॉग संचार, नेटवर्क सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, नियंत्रण प्रणाली आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ये कोर्स टेक्नोलॉजी की नॉलेज देता है। इस कोर्स के बाद करियर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे की आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग बन सकते है।

छात्र को 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 12वीं में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स विषय होना अनिवार्य है। छात्रों को 12वीं में कम से कम 50% से 60% अंक लाने होते हैं। अलग-अलग कॉलेजों में अंकों की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है। आरक्षित वर्ग को कुछ छूट मिल सकती है।

आज का युग डिजिटल का है। हर काम अब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या वलाउड के जरिए हो रहा है—चाहे बैंकिंग हो, ऑफिस वर्क, पढ़ाई या सोशल मीडिया। लेकिन जिस तेजी से डिजिटल तकनीक ने ज़िंदगी आसान की है, उतनी ही तेजी से बढ़े हैं डिजिटल अपराध। हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग जैसे मामलों की बाढ़ आ गई है। ऐसे में इन अपराधों की तह तक जाने और सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं—डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। इन्हें अक्सर स्क्रीन के पीछे का जासूस या डिजिटल डॉट डिटेक्टिव भी कहा जाता है। इनकी पहचान न तो वेदांते से होती है, न ही किसी इथियोर से, बल्कि इनका सबसे बड़ा हथियार होता है—तकनीक की गहरी समझ और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कला।

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट वह प्रोफेशनल होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड ड्राइव, ईमेल, सोशल मीडिया या क्लाउड जैसे डिजिटल स्रोतों से डिलीट या छिपाई गई जानकारी को रिकवर करता है और उसे कानूनी सबूत के रूप में पेश करता है।

अगर किसी ने ऑनलाइन बैंक फॉड किया है, या किसी अपराधी ने मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो ऐसे मामलों में यह एक्सपर्ट उन मिटाए गए डेटा को फिर से खोज निकालता है. ये कोर्ट में पेश करने योग्य फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि अपराधी को सजा मिल सके.

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम बेहद पेचीदा और संवेदनशील होता है। उन्हें हर बिट और बाइट को सबूत में बदलना होता है। इनके काम में शामिल होते हैं -

- ▶ डिलीट हुए डेटा, ईमेल या कॉल रिकॉर्ड को रिकवर करना
- ▶ वायरस या मेलवेयर के जरिए की गई छेड़छाड़ का पता लगाना
- ▶ कंप्यूटर या मोबाइल में छिपाई गई फाइलों को ट्रेस करना
- ▶ साइबर क्राइम, बैंक फॉड, हैकिंग की जांच करना
- ▶ डिजिटल सबूतों की वैधानिक रिपोर्ट तैयार करना
- ▶ कोर्ट और लॉ एजेंसियों को केस में तकनीकी सपोर्ट देना
- ▶ इन एक्सपर्ट्स को कई बार सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच, या साइबर क्राइम सेल के साथ काम करने का मौका मिलता है. इसके अलावा कई बार निजी कंपनियां और बैंक भी इन्हें साइबर सुरक्षा के लिए हायर करते हैं.

डिजिटल फॉरेंसिक्स का प्रोफेशन बनने के लिए साइंस य टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड जरूरी होता है, लेकिन अब लॉ

और क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें करियर की राह खुल चुकी है.

जैसे-जैसे डिजिटल क्राइम बढ़ रहा है, वैसे-वैसे डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक्सपर्ट्स विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं -

- लॉ एजेंसियां - CBI, ED, क्राइम ब्रांच, पुलिस साइबर सेल
- ज्यूडिशियल सेक्टर - कोर्ट केसों में डिजिटल सबूत जुटाने में सहयोग
- कॉर्पोरेट सेक्टर- साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में
- किंग और फिनटेक कंपनियां - फॉड डिटेक्शन टीम का हिस्सा
- प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स - स्वतंत्र जांच एजेंसियों के साथ
- फीलांस या कंसल्टेंट - लॉ फर्मस, स्टार्टअप्स, पत्रकारों के साथ सहयोग

क्या आप स्क्रीन के पीछे से सच उजागर करना चाहते हैं? डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनकर आप साइबर अपराधों का पर्दाफाश कर सकते हैं। यह वो प्रोफेशन है जहाँ तकनीक, सस्पेंस और न्याय साथ चलते हैं—एक ऐसा करियर जो हर दिन एक नई कहानी बनाता है।



डिजिटल फॉरेंसिक सिर्फ एक करियर नहीं
बल्कि भविष्य की सबसे जरूरी विशेषज्ञता
बनती जा रही है

हर सेक्टर डिजिटल हो रहा है—इसका मतलब अपराध भी डिजिटल हो रहे हैं

भारत में नया डेटा संरक्षण कानून लागू होगा
से अब कंपनियों को प्रोफेशनल जांच सेवाओं
की जरूरत पड़ रही है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डिजिटल फॉरेंसिक की जांच को और तेज बना रहा है

देशभर में ट्रेन किए गए डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोफेशनल्स की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है



जैसे-जैसे दुनिया स्क्रीन पर सिमट रही है, वैसे-वैसे अपराध भी टेक्नोलॉजी की आड़ में छिपते जा रहे हैं। लेकिन सच चाहे जितना भी गहरा छुपा हो, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे सामने लाने की ताकत रखते हैं। अगर आपको तकनीक, जांच और न्याय में रुचि है, तो यह फील्ड आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है।

देश में किशोरों व युवाओं को स्वयंसेवी कार्यों में लगाने वाली तमाम सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं। इनमें से किसी के साथ जुड़कर आप वॉलंटियरिंग की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं और समाज को

बेहतर के लिए बिना किसी वेतन के या फिर मामूली स्ट्राइपेंड पर काम करना चाहता है, उसे वॉलंटियर कहते हैं। इस तरह सामाजिक बदलाव के लिए काम करने से आपको मानसिक संतोष मिलता है। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, आगे आपके करियर में भी फायदा मिलता है।

आपका शहर, कस्बे या गांव में ऐसे लोग होंगे, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। वे फुटपाथ पर या अन्यत्र खुले में ही गुजारा करते हैं। आप ऐसे लोगों को नाश्ता, खाना, सड़क के दिनों में के समय भी आप वॉलंटियर के रूप में सहयोग कर सकते हैं।

पर्यावरण की खातिर

पर्यावरण को लेकर आज किसी छोटे

शहर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चिंता व्याप्त है। आप अपने शहर, कस्बे के पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए पौधे लगाने से लेकर प्रदूषण कम करने के तमाम प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।

कई अस्पतालों, संस्थाओं को नेत्र शिविर या रक्तदान शिविर जैसे कई अभियानों के लिए स्वयंसेवक चाहिए होते हैं। इसी तरह कई अनाथालय, सीनियर सिटिजन सेंटर आदि को भी वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। आप ऐसे मौकों पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

कई सामाजिक संस्थाएं अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, जर्नल आदि को चलाने और ऑनलाइन मार्केटिंग व कम्युनिकेशन के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेती हैं। यदि आपके पास कम्यूटर और इंटरनेट है तथा आप थोड़ी टैक्निकल, डिजिटल जागरूकता रखते हैं, तो किसी संस्था को

इन कार्यों में मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस तरह की समाज सेवा आप घर बैठे ही कर सकते हैं!

नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) देश सेवा व समाज सेवा के लिए एक बेहतरीन संगठन है। इसमें एक तरह की बैसिक मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह एनसीसी युवाओं को सैन्य सेवाओं में शामिल होने के लिए भी प्रेरक वातावरण तैयार करता है। यही नहीं, कई सैन्य सेवाओं में एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को तर्जनी भी दी जाती है। एनसीसी के कैडेटों को कई तरह के सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। इसी तरह भारत स्काउट एंड गाइड एक ऐसा संगठन है, जो स्कूली बच्चों के भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की दिशा में काम करता है। यह संगठन स्कूली बच्चों को कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी लगाता है।



इजराइल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी

कहा- राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे; जंग रोकने के लिए 5 शर्तें रखीं

एजेंसी

तेल अवीव, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी। काट्ज ने कहा, 'अगर हमारा इजराइल की शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा।' यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले काट्ज ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति दी थी। काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- गाजा का हाल राफा और बैत हनुन शहरों जैसा हो सकता है, जो



जबाब पर काट्ज ने 20 अगस्त को गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी। इसके लिए उन्होंने करीब 60 हजार एक्स्ट्रा सैनिकों (रिजर्व

फोर्स) को ड्यूटी पर बुलाने का भी आदेश दिया। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1.30 लाख सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। सैनिकों को ड्यूटी जॉइन करने से कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40-50 हजार सैनिक बुलाए जाएंगे। दूसरी खेप नवंबर-दिसंबर में और तीसरी फरवरी-मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। गाजा सिटी पर कब्जे के इस अभियान को गिदोनहस चेरिएट्स-बी नाम दिया गया है। इस दौरान पहले से ड्यूटी कर रहे

है। वहीं एक दूसरे इलाके, जबालिया में गिवाती ब्रिगेड कर्फू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। यह अभियान कई स्टेप में चलेगा। सबसे पहले नागरिकों को गाजा सिटी खाली करने का नोटिस मिलेगा। इसके लिए अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इसके बाद सेना शहर को चारों तरफ से घेरकर अंदर बढ़ेगी। इजराइल ने गाजा सिटी से लगभग 10 लाख लोगों को साउथ गाजा भेजने का प्लान बनाया है। इसके लिए राहत केंद्र, टेंट और फील्ड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। खान युनिस में भी यूरोपियन अस्पताल फिर से शुरू किया जाएगा। इजराइल का मकसद गाजा सिटी में उन इलाकों में

घुसना है, जहां हमारा के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजराइली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की है। इजराइली सेना (आईडीएफ) के मुताबिक गाजा पट्टी के लगभग 75% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। गाजा सिटी उस 25% इलाके में है, जो आईडीएफ के कब्जे में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि गाजा में भुखमरी अब नियंत्रण से बाहर है।

हमारा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि जंग शुरू होने के बाद से कुपोषण से मरने वालों की संख्या 170 हो गई है, जिनमें 95 बच्चे हैं।

कोलंबिया में एयरबेस के पास ट्रक में ब्लास्ट

कोकीन की खेती नष्ट करने जा रहे पुलिस हेलिकॉप्टर पर भी ड्रोन हमला; अबतक 18 की मौत

एजेंसी

बोगोटा, कोलंबिया में गुरुवार को दो अलग-अलग हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया के कैली शहर में गुरुवार को एयर बेस के पास एक ट्रक में बम विस्फोट हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 71 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका मार्को फिदेल सुआरेज सैन्य एविएशन स्कूल के पास हुआ। इससे कुछ घंटे पहले, कोकीन की फसलों को खत्म करने के लिए जा रहे पुलिसकर्मियों के हेलिकॉप्टर पर ड्रोन से हमला हुआ। जिसमें 12 पुलिस अधिकारी मारे गए



थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने कहा कि इन हमलों के पीछे विद्रोही संगठन एफएआरसी के गुप्तों का हाथ है। एफएआरसी का मकसद कोलंबियन सरकार को उखाड़ फेंकना

लोगों की जानकारी देने वालों को इनम देने की घोषणा की। प्रत्यक्षदर्शी ने एफएफपी न्यूज को बताया कि एयर बेस के पास किसी चीज के फटने की तेज आवाज आई। घटना के बाद आसपास के कई इमारतों और स्कूलों को खाली करा लिया गया है। साथ ही मेयर ने शहर में बड़े ट्रकों के ट्रैफ़ी पर रोक लगाने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री पेड्रो संचेज ने विस्फोट को 'आतंकवादी हमला' बताया और इसके लिए 'नाकों काटेल (ड्रग्स तस्करी करने वाला गिरोह) शुष गल्फ क्लान' को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, राष्ट्रपति और सैन्य नेतृत्व ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आज एक विशेष बैठक बुलाई है। कोलंबिया में

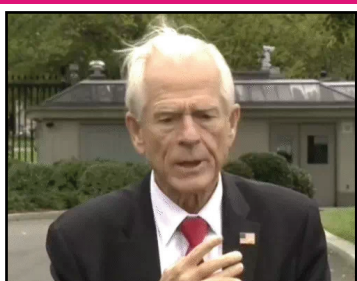
ड्रग्स की खेती, खासकर कोका की खेती होती है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है, जो वैश्विक कोकीन आपूर्ति का लगभग 60-70% हिस्सा पैदा करता है। कोकीन का पौधा कोलंबिया के दूरदराज और गरीब इलाकों जैसे नारीनो, काउका, पुदुमायो, और कैकेटा में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 2023 में, कोलंबिया में कोका की खेती 2.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो 2022 की तुलना में 10% अधिक है। कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और सरकारी उपस्थिति का अभाव कोका की खेती को बढ़ावा देता है।

ट्रम्प के सलाहकार बोले-भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा

इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद ऊंचे दाम पर बेचती हैं, इसलिए टैरिफ जरूरी

एजेंसी

वॉशिंगटन डीसी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए



पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि वे हमें सामान बेचकर मिलने

वाले पैसे से रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे तेल कंपनियां खूब पैसा कमाती हैं। इसलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। नवारो ने कहा, ट्रम्प ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, 27 अगस्त से लागू होगा।

इससे पहले ट्रम्प जुलाई में भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में

भारतीय सामान के आयात पर अमेरिका में 50% टैरिफ देना होगा। मशहूर अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने अमेरिका के भारत पर भारी टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला अमेरिकी विदेश नीति के लिए नुकसान भरा है।

इससे पहले अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका-भारत रिश्तों में आई गिरावट को नहीं रोका गया तो यह रणनीतिक गलती होगी।

नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं...पीएम मोदी के गयाजी दौरे पर लालू यादव का तंज



एजेंसी

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले उन पर तंज कसते हुए कहा कि वह (प्रधानमंत्री) राज्य में नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान कर रहे। पर एक वीडियो शेयर करते हुए, कथित वोट चोरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए, राजद प्रमुख ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान (मृत्यु के बाद का अनुष्ठान) करने गया आ रहे हैं। वीडियो में पिंडदान वाले अपने तंज के साथ, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कथित वोट चोरी, अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब बिहार स्थित गयाजी को पवित्र माना जाता है और हिंदुओं में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए यह स्थान लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस यात्रा का कोई लाभ नहीं है। किशोर ने कहा, रप्रधानमंत्री मोदी पिछले तीन-चार महीनों में तीन बार बिहार आ चुके

हैं। उनके हर दौरे पर बिहार की गरीब जनता के करोड़ों रुपये खर्च हुए... बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? बिहार से पलायन कब रुकेगा? बिहार के बच्चों को मजदूरी के लिए गुजरात कब नहीं जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच, बिहार दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गयाजी से बिहार के लिए 13000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैम्पस में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- डट मोदी ने कहा कि 'बिहार की धरती से लिया कोई संकल्प खाली नहीं जाता है। पहलगा म अटक के बाद मैंने बिहार से संकल्प लिया था

'पाक सेनाध्यक्ष ने मानी सच्चाई, भारत मर्सिडीज, पाकिस्तान डंपर'

राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं आपका ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो फेरारी की तरह हाईवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो ट्रक सान किसका होगा?

एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भारत की तुलना एक लज्जारी कार और अपने देश की तुलना एक डंप ट्रक से करने की विचित्र कोशिश का उपहास करते हुए कहा कि यह टिप्पणी अपने आप में पाकिस्तान की विफलता की स्वीकारोक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं आपका ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की ओर



आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो फेरारी की तरह हाईवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो नुकसान किसका होगा? राजनाथ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज और फेरारी जैसी है। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से

राजनाथ सिंह ने असीम मुनीर पर कसा तंज

हालत में है, तो यह उनकी अपनी विफलता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक स्वीकारोक्ति मानता हूँ। मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता। अगर हम इस गंभीर चेतावनी के पीछे छिपे ऐतिहासिक संकेत पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। और हाँ, अगर हम इस पर ध्यान दें और इसके लिए तैयारी करें, तो भारत ऐसी चेतावनियों का काररा जवाब देने में सक्षम है। उनकी यह टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में असीम मुनीर की टिप्पणियों के जवाब में आई है। मुनीर ने पलोरिडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जिसे उन्होंने खुद एक अशिष्ट सादृश्य बताया था, कहा था। उन्होंने पूछा, भारत फेरारी की तरह हाईवे पर आ रही एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक हैं।

व्यवस्था को खोखला करने की इजाजत नहीं मिलेगी

जम्मू-कश्मीर चूँकि लंबे समय से आतंकी हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील पदों पर बैठे लोग सुरक्षा तंत्र को कमजोर न करें। देखा जाये तो सरकारी नौकरी करदाताओं के पैसे से मिलती है।

एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दो सरकारी

जम्मू-कश्मीर ने आतंकी कनेक्शन वाले 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त

कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। आरोप है कि इनकी सलिपता आतंकवादी गतिविधियों या उनके समर्थन से जुड़ी हुई थी। हम आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, हाल के वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने कई ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त किया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों के लिए सहायता प्रदान करते रहे हैं। देखा जाये तो आतंकवाद का एक बड़ा खतरा यह है कि उसका नेटवर्क केवल जंगलों या सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं



रहता, बल्कि प्रशासन और व्यवस्था तक भी पहुँचने की कोशिश करता है। सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई यह

जम्मू-कश्मीर चूँकि लंबे समय से आतंकी हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील पदों पर बैठे लोग सुरक्षा तंत्र को कमजोर न करें। देखा जाये तो सरकारी नौकरी करदाताओं के पैसे से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद या अलगाववाद को समर्थन देता है, तो उसका वेतन उसी व्यवस्था से जाता है जिसे वह कमजोर कर रहा है। यह व्यवस्था के साथ धोखा है। बर्खास्तगी इसी विरोधाभास को समाप्त करने की

जगन रेड्डी के साक्षी टीवी पर मानहानि का मुकदमा, तिरुमाला मंदिर बोर्ड प्रमुख ने 10 करोड़ का मुआवजा मांगा

नायडू ने दावा किया कि वॉर्ल्डस आरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाले साक्षी टीवी और उसके समाचार पत्र ने 10 अगस्त और 14 अगस्त, 2025 को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और टीटीडी बोर्ड के लिए उनके काम को बदनाम करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ रिपोर्ट प्रकाशित की।

एजेंसी

तिरुमाला तिरुपति देवस्थान (टीटीडी) बोर्ड के अध्यक्ष बोलिनेनी राजगोपाल नायडू (बीआर नायडू), जो टीवी5 तेलुगु समाचार चैनल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने साक्षी टीवी और साक्षी समाचार पत्र को कानूनी नोटिस भेजकर अपमानजनक रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। 9 और 10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। नायडू ने दावा किया कि वॉर्ल्डस आरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाले



साक्षी टीवी और उसके समाचार पत्र ने 10 अगस्त और 14 अगस्त, 2025 को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और टीटीडी बोर्ड के लिए उनके काम को बदनाम करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने इस कवरेज को टीवी5 में उनकी भूमिका के कारण उनके खिलाफ एक बड़ी सजिशा का हिस्सा बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि टीवी5 निष्पक्ष, निष्पक्ष समाचार प्रदान करता है

कोशिश है। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि केवल कथित सत्यता के आधार पर सेवा समाप्त करना उचित प्रक्रिया के खिलाफ है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और सबूत की मजबूती अनिवार्य है, वरना यह निर्णय लोग सुरक्षा तंत्र को कमजोर न करें। लेकिन अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकवाद मुक्त कश्मीर की दिशा में कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाल के वर्षों में न केवल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बढ़े हैं, बल्कि उनके आर्थिक और संस्थागत समर्थन काटने की रणनीति भी अपनाई गई है।